साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 2 | अंक : 40 | गोंदिया : गुरुवार,. .12 से 18 मई 2022 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5

भाजपा के पूर्ण बहुमत के बावजूद राष्ट्रवादी व जनता की पार्टी का गठबंधन हुआ सत्ता पर काबिज

गोंदिया जिला परिषद में अनोखा गठबंधन : भाजपा के पंकज रहांगडाले अध्यक्ष राष्ट्रवादी के यशवंत गणवीर उपाध्यक्ष निर्वाचित

जिले के विकास के लिए वरिष्ठों के निर्देश पर गोंदिया जिला परिषद में भाजपा व राष्ट्रवादी तथा जनता की पार्टी चाबी संघटना से गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर किया गया है, ताकि जिले में विकास तीव्र गति से हो सके।

- विधायक विजय रहांगडाले

जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रवादी का गठबंधन जिले के विकास के लिए किया गया है। पक्ष के वरिष्ठ नेता तथा सांसद प्रफुल पटेल के निर्देशानुसार विकास कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

- पूर्व विधायक राजेंद्र जैन

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव आखिरकार 10 मई को संपन्न हुए। उपरोक्त चुनाव में एक नया अनोखा गठबंधन सामने आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पंकज रहांगडाले अध्यक्ष व राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के यशवंत गणवीर उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए।

विशेष यह है की गोंदिया जिला परिषद में भाजपा को पूर्ण बहुमत होने के बावजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनता की पार्टी चाबी व निर्दलियों का गठबंधन सत्ता पर काबिज हुआ। गौरतलब है कि गोंदिया जिला परिषद चुनाव में एक राजनीति का नया समीकरण देखने को मिला। जिसमें पूर्ण बहुमत के बावजूद भाजपा द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस व जनता की पार्टी चाबी से गठबंधन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के पंकज रहांगडाले 40 मत लेकर अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से यशवंत गणवीर भी 40 मत लेकर उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार उषा मेंढे को 13 व उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र कटरे को 13 मत प्राप्त हुए।

उल्लेखनीय है कि राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना व कांग्रेस की महाविकास आघाडी के साथ सरकार चल रही है। वहीं विपक्ष में भाजपा महाविकास आघाडी सरकार पर आक्रमक है। लेकिन गोंदिया में महाविकास आघाडी की सहयोगी कांग्रेस को इस गठबंधन से दूर रख एक नया गठबंधन सामने आया है। गोंदिया जिला परिषद की 53 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 26, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 8, जनता की पार्टी 4 व निर्दलीय 2 सदस्य तथा भारतीय कांग्रेस के 13 सदस्य है। चुनाव के 2 दिनों पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी को दो निर्दलीयों द्वारा समर्थन दिया गया था, जिससे वह पूर्ण बहुमत की स्थिति में पहुंच चुके थे। लेकिन गोंदिया जिला परिषद में इस गठबंधन से एक बड़ा विपक्ष खत्म हो गया है तथा विपक्ष में अब सिर्फ कांग्रेस के 13 सदस्य ही बचे हैं।

उपरोक्त चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव की कमान विधायक विजय रहांगडाले, भाजपा जिला अध्यक्ष केशव मानकर, पूर्व विधायक व पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत पटले, खोमेश्वर रहांगडाले, पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, संजय पुराम, विजय शिवनकर, वीरेंद्र अंजनकर द्वारा संभाली गई थी। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, नरेश महेश्वरी, गंगाधर परशुरामकर व अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे तथा कांग्रेस की ओर से अशोक गप्पू गुप्ता, अमर वराडे, पी.जी. कटरे प्रमुख रुप से उपस्थित थे।

UNITED
SUPERSPECIALITY HOSPITAL
AND TRAUMA CENTER

जाहिर आमंत्रण

गोंदिया का प्रथम 100 बेड उच्च क्षमता का

युनाईटेड सुपरस्पेशलिटी हॉस्पीटल
एण्ड ट्रामा सेंटर

भव्य शुभारंभ

12 मई 2022 गुरुवार
संध्या 5.00 बजे

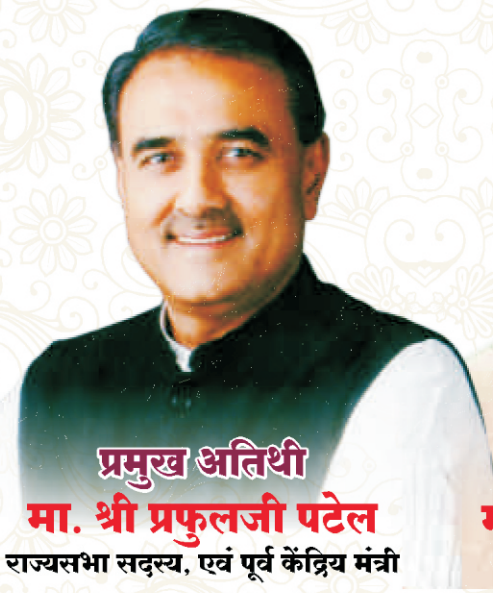

प्रमुख अतिथी
मा. श्री प्रफुलजी पटेल
राज्यसभा सदस्य, एवं पूर्व केंद्रिय मंत्री

शुभ हस्ते
मा. श्री शिवराजसिंहजी चौहान
माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रमुख अतिथी

मा. श्री सुनिलजी केदार
पशुसंवर्धन मंत्री, महाराष्ट्र

मा. श्री नानाभाऊ पटोले
विधायक, साकोली

मा. श्री सुनिलजी मेंढे
सांसद, भंडारा-गोंदिया

मा. श्री परिणयजी फुके
विधान परिषद सदस्य

मा. श्री विनोदजी अग्रवाल
विधायक,गोंदिया

मा. श्री आशिषजी जायसवाल
विधायक, रामटेक

मा. श्री विजयजी रहांगडाले
विधायक, तिरोडा

मा. श्री हंसराजजी अहीर
पूर्व केन्द्रिय मंत्री

मा. कु. हिना कावरे
विधायक, लांजी

मा. श्री प्रदिपजी (गुड्डा) जायसवाल
विधायक, बारासिवनी

मा. श्री गौशिंकरजी विसेन
विधायक, बालाघाट

मा. श्री मोहनभाऊ मते
विधायक, नागपुर-दक्षिण

मा. श्री राजुभाऊ कारेमोरे
विधायक, तुमसर

मा. श्री सहेषरामजी कोरोटे
विधायक, देवरी-आमगांव

मा. श्री मनोहरजी चंद्रिकापुरे
विधायक, अर्जुनी/मोर.

मा. श्री नानाभाऊ पंचबुद्धे
पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. श्री राजकुमारजी बडोले
पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. श्री मधुकरजी कुकडे
पूर्व सांसद, भंडारा-गोंदिया

मा. श्री शिशुपालजी पटले
पूर्व सांसद, भंडारा-गोंदिया

मा. श्री अमरभाऊ काले
पूर्व विधायक, आर्वी

मा. श्री गोपालदासजी अग्रवाल
पूर्व विधायक, गोंदिया

मा. श्री राजेन्द्रजी जैन
पूर्व विधान परिषद सदस्य

मा. श्री गिरीषजी व्यास
पूर्व विधान परिषद सदस्य

मा. श्री केशवरावजी मानकर
पूर्व विधान परिषद सदस्य

मा. श्री हेमंतभाऊ पटले
पूर्व विधायक, गोरेगांव

मा. श्री रमेशभाऊ कुथे
पूर्व विधायक, गोंदिया

मा. श्री के. डी. देशमुख
पूर्व विधायक, कटंगी

मा. श्री सुनिलभाऊ फुंडे
संचालक, वि.डी.सी.सी.बैंक

सम्माननीय अतिथियों का
हार्दिक स्वागत

स्वागताकांक्षी
युनाईटेड परिवार, गोंदिया

संपादकीय

वक्त की जरुरत

खुदरा और थोक महंगाई दोनों नित नए रेकार्ड बना रहे हैं।

महंगाई की रफ्तार थामने के लिए आखिरकार रिजर्व बैंक को अपना सबसे बड़ा हथियार चलाना ही पड़ा। करीब पौने चार साल बाद बुधवार को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर 0.40 फीसद बढ़ाते हुए 4.40 फीसद कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि एमपीसी की यह बैठक बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के हुई। इसलिए समिति के इस फैसले से सबका हैरान होना लाजिमी है।

लेकिन यह फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया। एमपीसी की पिछली दो-तीन बैठकों से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि केंद्रीय बैंक कभी भी नीतिगत दरें बढ़ा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते भी रहे हैं कि नीतिगत दरों के मामले में उदार रुख को बहुत लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता।

पिछले महीने एमपीसी की बैठक में उन्होंने साफ कहा था कि बैंक की प्राथमिकता महंगाई को थामना है। इसलिए जल्दी ही नीतिगत दरें बढ़ाई जा सकती हैं। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी रिजर्व बैंक की मजबूरी इसलिए बन गई कि महंगाई की दर उसके छह फीसद के निर्धारित दायरे से भी ऊपर निकल गई है। ऐसे में रिजर्व बैंक कब तक चुप बैठता?

गौरतलब है कि महंगाई को लेकर लंबे समय से हाहाकार मचा है। खुदरा और थोक महंगाई दोनों नित नए रेकार्ड बना रहे हैं। खाद्य वस्तुओं और खाद्य तेलों सहित जिंसों और धातुओं के बाजार में भारी तेजी बनी हुई है। मार्च के महीने में ही महंगाई दर 6.95 फीसद पर पहुंच गई थी, जो सत्रह महीने में सबसे ज्यादा थी।

ऐसे में रिजर्व बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह खुदरा महंगाई दर को निर्धारित छह फीसद से ऊपर न जाने दे। इसीलिए अब एमपीसी के पास कोई चारा नहीं रह गया था, सिवाय इसके कि वह नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का कठोर कदम उठाती। इसलिए भी कि अगर महंगाई इसी तरह बेकाबू होती रही तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने लगेंगे।

हालांकि महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। दो साल तक कोविड महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों ही पहले से जूझ रहे हैं। हालात जैसे तैसे काबू में आने शुरु हुए तो रुस-यूक्रेन युद्ध छिड़ गया। इस वैश्विक संकट ने नए सिरे से मुश्किलें खड़ी कर दीं। सबसे ज्यादा मार कच्चे तेल के दामों से पड़ी।

भारत में आज महंगाई जिस रेकार्ड स्तर पर पहुंच गई है, उसका बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हैं। आज भी पेट्रोल सौ रुपए से ऊपर बिक रहा है। मुश्किल यह है कि यूक्रेन संकट कितना लंबा खिंचेगा, कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर महंगाई और बढ़ी तो देश नए संकट में फंस जाएगा।

इसीलिए एमपीसी ने लगे हाथ यह भी कह दिया कि वह अगले महीने यानी जून में भी नीतिगत दरों में और इजाफा कर सकती है। अब जिस तरह के हालात हैं उनमें रिजर्व बैंक देखो और इंतजार करो की नीति पर नहीं चल सकता। यह तो निश्चित है कि नीतिगत दरें बढ़ने से व्यावसायिक बैंक भी कर्ज महंगा करेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ना तय है।

मांग में भी कमी आएगी, पर एमपीसी का यह कदम वक्त की जरुरत भी है। पिछले कुछ समय में अमेरिका सहित दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी महंगाई से निपटने के लिए दरें बढ़ाने जैसा कदम उठाया है। पिछले हयते रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त संबंधी जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी साफ कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में संतुलन साधने की जरुरत है। नीतिगत दरें बढ़ाने का फैसला इसी दिशा में बड़ा कदम है।

हकीकत और फसाना

कोरोना की दूसरी लहर भारत में सबसे भयावह रुप में उभरी थी।

भारत सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में। इसे लेकर कई विदेशी संगठनों और शोध पत्रिकाओं ने भी अपने अनुमानित आंकड़े प्रकाशित किए, जिसमें मौतों की संख्या सरकार के बताए आंकड़े से कई गुना ज्यादा थी। सरकार शुरु से इसका खंडन करती रही है।

अब उसने 2020 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण के आधार पर तथ्य पेश करते हुए कहा है कि लांसेट जैसी कुछ पत्रिकाओं ने बेतुके ढंग से मौतों का आंकड़ा बढ़-चढ़ कर दिखाया और भारत को बदनाम करने की कोशिश की। नीति आयोग ने ऐसी एजंसियों को नसीहत भी दी है कि उन्हें ऐसे आंकड़े देने बंद कर देना चाहिए। नीति आयोग ने 2020 के आंकड़ों पर आधारित नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सीआरएस रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 2019 में कुल मौतें 76.4 लाख थीं, जो 2020 में 6.2 फीसद बढ़ कर 81.2 लाख हो गई थी। इस तरह 2019 की तुलना में 2020 के मृत्यु पंजीकरण में 4.75 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि लांसेट पत्रिका ने कोरोना की वजह से भारत में हुई मौतों का अनुमान चालीस लाख सत्तर हजार पेश किया था, जो दुनिया में सबसे अधिक है।

कोरोना की दूसरी लहर भारत में सबसे भयावह रुप में उभरी थी। उस दौरान अस्पतालों में बिस्तर खाली न होने, समुचित इलाज न मिल पाने की वजह से सबसे अधिक मौतें हुई थीं। सब जगह अफरा-तफरी का आलम था। उस दौरान बहुत सारे अस्पतालों में आक्सीजन की भारी कमी हो गई थी, जिसके चलते सरकार को दूसरे देशों से आक्सीजन मंगाना पड़ा।

आक्सीजन की कमी के चलते बहुत सारी मौतें हुई थीं। उस दौरान श्मशानों और कब्रिस्तानों में जगह न मिल पाने के कारण लाशें गंगा में बहाने या गंगा की ~~रेती पर दफनाने के प्रमाण भी सामने आए थे। कई जगह अतिरिक्त श्मशान बनाने~~ पड़े थे, खुले में शवदाह की व्यवस्था की गई थी, जहां रात-रात भर चिताएं जलती थीं। इसके चलते केंद्र और कुछ राज्य सरकारों को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी।

इन सारी स्थितियों को देखते हुए लोगों का अनुमान था कि भारी पैमाने पर मौतें हुई हैं, क्योंकि सामान्य मौतों के मामले में इस तरह अंतिम क्रिया को लेकर अफरा-तफरी कभी नहीं देखी गई। यानी श्मशानों की क्षमता से अधिक उनमें लाशें पहुंचने के कारण ही ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। इसलिए अब भी कई लोग सरकार के ताजा आंकड़ों पर शक जाहिर करें, तो हैरानी नहीं।

दरअसल, कोरोना से हुई मौतें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की नाकामी का भी पता देती हैं, इसलिए कई राज्यों में सरकारों ने वास्तविक संख्या छिपाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, संसद में भी एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि आक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। तब भी सरकार की तीखी आलोचना हुई थी।

बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोरोना से हुई मौतों पर सरकार को मुआवजा देना होगा। अभी तक उस दिशा में इसलिए आगे नहीं बढ़ा जा सका है कि कोरोना से हुई मौतों के स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं हैं। बहुत सारे अस्पतालों ने बहुत सारी मौतों की वजह कोरोना लिखा ही नहीं, जैसे आक्सीजन की कमी को मौत का कारण नहीं लिखा। अगर सरकार ने अस्पतालों के उसी ब्योरे को सही मान लिया है, तो इस रपट को सवालों से परे नहीं माना जा सकता।

खत्म हो राजद्रोह

अंतिम सुनवाई की बात करते हुए भी कोर्ट ने यही कहा कि उसे सबसे ज्यादा चिंता इस कानून के दुरुपयोग की है। इसीलिए यह भी जरुरी है कि अब इस चरण में आकर कानून का दुरुपयोग रोकने संबंधी प्रावधान करने जैसी दलीलों के चक्कर में न पड़ा जाए। 1962 के बहुचर्चित केदारनाथ सिंह जजमेंट में इसी उद्देश्य से राजद्रोह मामलों का दायरा कम किया गया था, लेकिन अब तक का अनुभव बताता है कि पुलिस और प्रशासन के रवैये पर इसका कोई असर नहीं पड़ा

राजद्रोह कानून खत्म करने संबंधी याचिकाओं पर और देरी को नामंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस सप्ताह के अंत तक हर हाल में अपना जवाब दाखिल कर दे। 5 मई से इस मामले में आखिरी सुनवाई शुरु होगी और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सुनवाई टालने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। लंबे समय से कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पणियों में जता चुका है कि औपनिवेशिक काल के इस कानून को अब जारी रखने का कोई तुक नहीं है। बावजूद इसके, किसी न किसी कारण से यह मामला टलता रहा है। दिलचस्प है कि बौद्धिक और न्यायिक हलकों में इस कानून को जारी रखने का कोई आग्रह बचा न रह जाने के बावजूद जितने दिन भी यह कानून है, इसके इस्तेमाल में कोई कमी नहीं देखने में आ रही। जहां जिस पार्टी की सरकार है, वही विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। असल में यह कानून है भी ऐसा कि इसे इस मकसद से इस्तेमाल करने में कोई अड़चन नहीं आती। आईपीसी की धारा 124-ए उन शब्दों और कार्यो के लिए तीन साल से लेकर आजीवन कैद तक की सजा का प्रावधान करती है जो सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना और विद्रोह भड़काने का प्रयास करते हों। एक तो नफरत, अवमानना और विद्रोह जैसे शब्द काफी व्यापक अर्थ रखते हैं। सो, किसी भी तरह के भाषण को इसके अंतर्गत डाला जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि गैरजमानती धाराओं के चलते इसकी चपेट में आने वालों का एक लंबे समय के लिए जेल जाना लगभग तय रहता है। अगर अंग्रेजी शासन का संदर्भ याद रखते हुए देखें तो तत्कालीन सरकार के लिए यह कानून बड़े काम की चीज था। अपने लेखों और भाषणों में अंग्रेज सरकार की तीखी आलोचना के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोई और मामला बनाना मुश्किल था। सो, अंग्रेजी सरकार इसी कानून के सहारे आजादी के योद्धाओं को लंबी अवधि के लिए जेल भेज दिया करती थी। अब स्वतंत्र, लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना पर सजा देना वास्तव में कानून का दुरुपयोग ही है। अंतिम सुनवाई की बात करते हुए भी कोर्ट ने यही कहा कि उसे सबसे ज्यादा चिंता इस कानून के दुरुपयोग की है। इसीलिए यह भी जरुरी है कि अब इस चरण में आकर कानून का दुरुपयोग रोकने संबंधी प्रावधान करने जैसी दलीलों के चक्कर में न पड़ा जाए। 1962 के बहुचर्चित केदारनाथ सिंह जजमेंट में इसी उद्देश्य से राजद्रोह मामलों का दायरा कम किया गया था, लेकिन अब तक का अनुभव बताता है कि पुलिस और प्रशासन के रवैये पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वक्त का तकाजा है कि और देर किए बगैर राजद्रोह (देशद्रोह) कानून को तत्काल समाप्त कर दिया जाए।

घातक माइक्रोप्लास्टिक

भारतीय वैज्ञानिक खोजेंगे इसे नष्ट करने का तरीका

महाराष्ट्र, कर्नाटक के खेतों में जमीन के अंदर 30 सेमी तक मौजूद

बुलंद गोंदिया - हमें रोजाना माइक्रोप्लास्टिक दिखाई देता है, पर हमें उसके बारे में पता नहीं होता। दूथपेस्ट और फेस स्क्रब में उपयुक्त माइक्रोबायड्स नामक कॉस्मेटिक में माइक्रोप्लास्टिक होता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान आदि कपड़ों को जब धोते हैं, तो वाशिंग मशीन में ये रेशे छोड़ते हैं। यही रेशे पानी में बह जाते हैं और बाद में सूक्ष्म कणों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक के कण बनते हैं। भारतीय वैज्ञानिक माइक्रोप्लास्टिक को नष्ट करने का रास्ता खोजेंगे। केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) ने देश के अलग-अलग अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर अध्ययन की योजना बनाई है। इसके लिए निजी अनुसंधान केंद्र और कंपनियों को भी जुड़ने का न्योता दिया गया है।

यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेंगी विश्वस्तरीय आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया इतिहास के रुप में निर्माण हो रहे यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व ट्रामा सेंटर जो जिले का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है का गुरुवार 12 मई को शुभारंभ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के हस्ते होंगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में राज्य सभा सांसद प्रफुल पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, राज्य के मंत्री सुनील केदार सहित प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहेंगी। यूनाइटेड हॉस्पिटल के संचालकों में से एक चिकित्सक डॉ अभिषेक भालोटिया ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बिस्तरों वाला जिले का पहला समर्पित सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय है। यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व किफायती स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ विकसित किया गया एक अत्याधुनिक सेंटर है। साथ ही समाज व अपनी जन्मस्थली में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रधान करने का उद्देश्य लेकर इसे शुरु किया गया है। जहां हमारा बचपन पोषित हुआ है तथा इस सपने को साकार करने में हमारे माता पिता की प्रेरणा व मार्गदर्शन की निरंतरता ही हमारी शक्ति है। साथ ही मरीजों व उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की भूमिका का निर्वहन करना ही मुख्य लक्ष्य तथा सभी प्रकार की आपातकालीन सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

यूनाइटेड हॉस्पिटल ट्रामा की उपलब्ध सुविधाएं

- स्तर 3 आघात देखभाल
- कैथ लैब के साथ कार्डियक यूनिट
- ब्रेन ट्रामा और टयूमर सर्जरी
- मिनिमल इनवेसिव स्पाइन सर्जरी
- ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी थूलियम लेजर और डायलिसिस सुविधाओं के साथ न्यूरो सर्जरी यूनिट
- एनआईसीयू के साथ उच्च जोखिम प्रसूति ईकाई
- उन्नति नेत्र विज्ञान इकाई और लसिक केंद्र
- उन्नत लेप्रोस्कोपीक सर्जरी तंत्रिका विज्ञान
- सामान्य सर्जरी व बालरोग समर्पित गहन देखभाल के साथ आईसीसीयू
- आधुनिक पैथोलॉजी प्रयोगशाला
- अत्याधुनिक ऑप्थल्म ओटी काम्प्लेक्स
- मॉडयूलर ओटी
- फ्लैट पैनल कार सिस्टम
- एक्स-रे सिस्टम
- 3डी यूएसजी फिलिप्स एफिनिटी 70
- कार्ल स्टोर्स लेप्रोस्कोपीक यूनिट हार्मोन विश्लेषण मशीन के साथ शिर्ष श्रेणी की पैथोलॉजी लैब
- एफएनएसी हिस्टोपैथोलॉजी सेवाए व अन्य सुविधाएं तथा 24 बाय 7 फार्मेसी एंबुलेंस तथा कैंटीन का समावेश है।

यूनाइटेड हॉस्पिटल मे शहर के चिकित्सा तज्ञ डॉ. दर्पण चौधरी, डॉ अभिषेक भालोटिया, डॉ वैभव नासरे, डॉ पराग जयपुरिया, डॉ. जूही भालोटिया, डॉ. पायल चौधरी, डॉ. शुभांगी नासरे, डॉ निधि जयपुरिया, डॉ. कुशल अग्रवाल व डॉ सचिन केलनका व सृष्टि केलनका अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

शासकीय मेडिकल कॉलेज गोंदिया के पहली बेच के उत्तीर्ण ९६ डॉक्टरों का

'युवाओं की आवाज' गैर राजकीय संगठन ने किया सत्कार

बुलंद गोंदिया - गोंदिया शासकीय मेडिकल कॉलेज कि वर्ष 2016 एमबीबीएस छात्रों की पहली बैच के उत्तीर्ण होने पर एनएमडी कॉलेज गोंदिया के ऑडिटोरियम में ग्रेजुएट सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर युवाओं की आवाज गैर राजकीय संगठन द्वारा सभी उत्तीर्ण डॉक्टरों का सत्कार किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन गोंदिया की जिलाधिकारी नयना गुंडे की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिसमें मेडिकल कॉलेज गोंदिया से सभी उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री प्रदान की गई ।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डीन डॉ के एस घोरपड़े, पूर्व डीन डॉ अजय केवलिया, डॉ नरेश तिरपुड़े, डॉ अपूर्व पावडे, डॉ विपी रुखमोडे, डॉ विपुल अंबादे मेडिकल अधीक्षक डॉ एन.के जायसवाल, समन्वयक डॉ प्रवीण जाधव, प्रमुख अतिथि के रुप में जिला शल्य चिकित्सक डॉ अमरीश मोहबे, आईएमए अध्यक्ष डॉ विकास जैन, रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्य, प्रिंसिपल एनएमडी कॉलेज शारदा महाजन, निखिल जैन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नितिन वानखेड़े, डॉ नितिन कापसे व मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों के प्रमुख प्रोफेसर, डॉक्टर उपस्थित थे। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में युवाओं की आवाज संगठन के अध्यक्ष सचिन रहांगडाले, जिला उपाध्यक्ष जाकिर खान व सचिव विजय रहांगडाले उपस्थित थे।

९५ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन उदगीर में क्षितीजा बापट के काव्यसंग्रह क्षितिजा पलीकडे का हुआ प्रकाशन

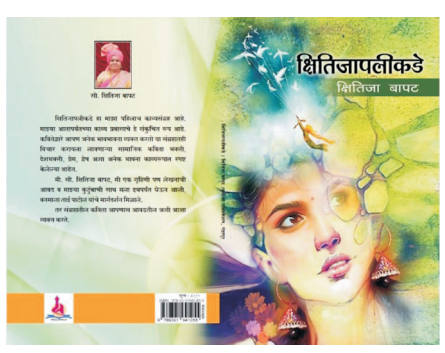

बुलंद गोंदिया - 95 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन उदगीर जिला लातूर में कवियत्री क्षितीजा बापट इनका काव्य संग्रह क्षितिजा पलीकडे महाराष्ट्र उदयगिरि महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम मे प्रकाशित किया गया। 36 जिले में 36 हिरकणी के विविध साहित्य यहां पर प्रकाशित हुए तथा यह कीर्तिमान महाराष्ट्र बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने वाला है। हिरकणी समूह की आधार स्तंभ वनमाला पाटील इनका विशेष योगदान रहा। सम्मेलन में नामी साहित्यिक रामचंद्र तिरुके, डॉ. माधव सूर्यवंशी, डॉ धनंजय गुडसरकर इनकी प्रमुख उपस्थिति थी।

क्षितिजा पलीकडे इस काव्य संग्रह द्वारा कवियत्री ने अनेक भाव-भावना व्यक्त की है। क्षितिजा बापट ने कहा कि मुझे काव्य संग्रह लिखने की काफी दिनों से इच्छा थी और इसका प्रकाशन बड़े साहित्य सम्मेलन में होने से मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे काव्य संग्रह लिखते समय हिरकणी ग्रुप की अध्यक्ष वनमाला पाटील का विशेष सहयोग रहा। संग्रह पाठकों के हृदय में स्थान निर्माण करें ऐसी आशा कवियत्री ने व्यक्त की है।

२ लाख पौधारोपण : गोंदिया जिले में होंगी हरियाली की चादर

बुलंद गोंदिया - भीषण गर्मी में भी पौधों को जीवित रखने के लिए सामाजिक वनीकरण विभाग द्वारा बच्चों की तरह पौधों की देखरेख की जा रही है। लाखों पौधों को जीवित रखने पानी दिया जा रहा है। ताकि सूर्य की तेज किरणों से पौधों को बचाया जा सके। इसका फायदा यह हो रहा है कि जिले के 181 किलोमीटर पर पौधे वृक्षों में तब्दील होकर परिसर हरियालीयुक्त हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए सामाजिक वनीकरण विभाग द्वारा पौधों की देखभाल का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि पानी को जीवन कहा जाता है। लेकिन जलस्तर को बनाए रखने के लिए पर्यावरण को संतुलित रखना भी बेहद जरुरी होता है। इसी उद्देश्य को लेकर सामाजिक वनीकरण विभाग के माध्यम से खुली भूमि पर तथा सड़कों के दोनों छोर पर पौधों का रोपण कर हरियाली बनाए रखने के लिए काम किया जाता है। गोंदिया जिले में सामाजिक वनीकरण विभाग व मनरेगा के माध्यम से 2 लाख 6 हजार 472 पौधों को वृक्षों में तब्दील करने के लिए जितोड़ मेहनत की जा रही है।

सांसद प्रफुल पटेल के निर्देशानुसार पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के मार्गदर्शन में

पंस चुनाव में चाबी, राकॉ बसपा, अपक्ष का गठबंधन

बुलंद गोंदिया - सांसद प्रफुल पटेल के निर्देशानुसार व पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के मार्गदर्शन में गोंदिया पंचायत समिति के चुनाव में चाबी संगठन, बसपा, अपक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस गठबंधन ने साथ मिलकर 18-18 मतों के साथ सभापती, उपसभापती के चुनाव में सभापती मुनेश रहांगडाले, उपसभापती नीरज उपवंशी विजयी हुये। सांसद प्रफुल पटेल के निर्देशानुसार व पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के मार्गदर्शन में इस चुनाव में निरीक्षक नरेश माहेश्वरी, गंगाधर परशुरामकर, राजू एन जैन, केतन तुरकर, अखिलेश सेठ, कुंदन कटारे, बालकृष्ण पटले, रवि पटले, सुनील पटले का योगदान महत्वपूर्ण रहा।

राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन, रेलटोली में नवनिर्वाचित गोंदिया पंचायत समिति के उपसभापती नीरज उपवंशी व सभी पंचायत समिति सदस्य शिवलाल जमरे, शंकर टेंभरे, वंदना पटले, नंदिनी लिल्हारे, सरला लिंकेश चिखलोंडे, राजेश जमरे का पुष्पगुछ देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओ ने नवनिर्वाचित सभापती व उपसभापती का अभिनन्दन कर भविष्य की शुभकामनाये दी। इस अवसर पर गणेश बरडे, घनश्याम मस्करे, अश्विनी पटले, नितीन टेभरें, कारण टेकाम, सौरभ रोकडे, नागरत्न बन्सोड, कल्लू मस्करे, महेंद्र बघेले, लव माटे, बाल्या कोसरकर, शरभ मिश्रा, वामन गेडाम व अन्य उपस्थित थे।

सामान्य दर्जे की टिकट रेलवे काउंटर से पूर्ववत रुप से दी जाए

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे समिति ने सांसद सुनील मेंढे को ज्ञापन सौंपकर की मांग

बुलंद गोंदिया - पिछले 2 वर्षो से कोरोना के चलते रेल विभाग में सामान्य दर्जे की सभी काउंटर टिकट बंद कर दी गई है। लेकिन अब केवल राज्य में नहीं बल्कि सारे देश में कोरोना नियंत्रण है। इसी दौरान रेलवे में लंबी दूरी की अनेक गाड़ियों को स्पेशल गाड़ी का दर्जा देकर शुरु किया है, जिसमें पूर्व रिजर्वेशन करके ही यात्रा की जा सकती है। इसके लिए यात्रियों को नियमित टिकट दर की तुलना में लगभग दोगुना किराया भरना पड़ता है। लेकिन सभी पैसेंजर व लोकल गाड़ियां पूर्ववत शुरु नहीं की हुई है। जिसके कारण आम यात्री परेशान हैं। लोकल गाड़ियां के लिए मासिक टिकट देनी तो शुरु कर दी गई है। लेकिन गाड़ियों की संख्या सीमित होने से यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। एक ओर लोकल तथा पैसेंजर गाड़ी पर्याप्त संख्या में शुरु होने व दूसरी ओर एक्सप्रेस गाड़ियों में जनरल टिकट शुरु ना होने के कारण यात्री परेशान हैं। लंबी दूरी की गाड़ी बाकी स्टेशनों पर नहीं रुकती। जबकि ज्यादा हजारों नागरिक ऐसे होते हैं कि जिन्हें रोजमर्रा के काम के लिए गांव से नजदीकी शहर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर पिछले 4 माह से अधिक समय से बसों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में यात्रियों के लिए बड़ी समस्या निर्माण हो रही है। इसी समस्या को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे समिति ने सांसद सुनील मेंढे को ज्ञापन सौंपकर सभी ट्रेनों की काउंटर टिकट पूर्ववत की जाने मांग की गई। इसमें प्रमुख रुप से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे समिति के सदस्य सूरज नसीने, दिव्या भगत पारधी, हरीश अग्रवाल, राजेंद्र कावळे, अखिल नायक उपस्थित थे।

मानसून के पूर्व शहर के बड़े-छोटे नालों की करे सफाई - जितेंद्र पंचबुद्धे

बुलंद गोंदिया - गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी बड़े और छोटे नालों की सफाई मानसून के पूर्व किए जाने की मांग का निवेदन पूर्व सभापति जितेंद्र ताराचंद पंचबुद्धे द्वारा नगर परिषद के प्रशासक व मुख्य अधिकारी करण चौहान को देकर की है। अपने निवेदन में उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों में मानसून की शुरुआत होने वाली है तथा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी नालों की सफाई समय के पूर्व करना आवश्यक है। क्योंकि गत वर्ष नगर परिषद के माध्यम से नालों की सफाई न होने के चलते 2 वर्षो से गाद व वह छोटी-छोटी झाड़ियां उग आई है। जिससे बारिश का पानी निकलने में काफी परेशानी होगी तथा मार्गो पर पानी भरने के साथ ही शहर के निचले क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के मकानों में भी पानी भर सकता है। जिसके चलते उपरोक्त पत्र व निवेदन के आधार पर नगर परिषद द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाए।

२ दुपहिया की भीषण टक्कर २ की मौत ४ जख्मी

बुलंद गोंदिया - गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गोंदिया-बालाघाट मार्ग पर ग्राम नागरा के समीप 7 मई की रात 11 से 11.30 बजे के दौरान 2 दुपहिया वाहनों की आमने सामने की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई व 4 लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार काटीबाजार टोला निवासी आदित्य गजानन इनवाते (18) व दिगंबर जयचंद इनवाते (21) अपने एक साथी के साथ दुपहिया वाहन पर काटी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आने वाली दुपहिया वाहन जिसमें ग्राम ढाकनी के 3 लोग शामिल थे। दोनों वाहनों की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई व दूसरे की उपचार के दौरान निजी चिकित्सालय में मौत हो गई और 4 जख्मीयों का उपचार चल रहा है। उपरोक्त घटना में बाजारटोला काटी निवासी आदित्य गजानंद इनवाते वह दिगंबर इनवाते की मौत हुई है। उपरोक्त मामले में गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस कर्मचारी कोकोड़े द्वारा ग्रामीण पुलिस थाने के निरीक्षक के मार्गदर्शन में कर रहे हैं।

खातिया ग्राम पंचायत में लाखों का घोटाला, दोषियों पर कार्रवाई न होने पर करेंगे आंदोलन - ललित तावाडे

बुलंद संवाददाता खातिया - गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खातिया के कार्यालय में लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अब तक दोषियों पर कार्रवाई न होने के चलते ग्रामवासियों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी है।

गौरतलब है कि गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खातिया ग्राम पंचायत में 15वे वित्त आयोग व ग्राम पंचायत के अन्य विकास निधि खातों में से कार्य न करते हुए चेक के माध्यम से निधि निकाल ली गई है। साथ ही मवेशियों के कोठे का अनुदान लाभार्थियों को न देते हुए राशि निकाली गई है। इस घोटाले की जानकारी सामने आने पर ग्राम के नागरिक ललित अर्जुन तावाडे, मूलचंद बहेकार, ग्राम पंचायत सदस्य महेश चौरे सहित अनेक नागरिकों द्वारा 25 फरवरी 2022 को जिलाधिकारी कार्यालय, खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति गोंदिया, विधायक विनोद अग्रवाल व संबंधित अन्य विभागों के कार्यालयों में निवेदन देकर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन शिकायत के 2 महीने के बावजूद अब तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई है।

इस संदर्भ में ललित तावाडे ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामवासियों द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि संबंधित दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही न होने से प्रशासन वेर वरिष्ठ अधिकारियों पर भी सवालिया निशान निर्माण हो रहा है।

मामले की जांच शुरु निलंबन का प्रस्ताव दिया

ग्राम पंचायत खातिया में विकास निधि के घोटाले के संदर्भ में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात मामले की जांच कर ग्राम सचिव सुभाष किरसाम के निलंबन का प्रस्ताव जिला परिषद के विभाग में भेजा गया है, तथा इस संदर्भ में जल्द ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज की जाएंगी।

- दिलीप खोटोले
खंड विकास अधिकारी, पंस. गोंदिया

क्या कोई मराठा आरक्षण की बात करेगा? - नरेंद्र मोहिते

नागपुर - देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव जोरशोर से मनाया जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता के कारण सभी जातियों और धर्मो के लोग सभी के साथ सद्भाव से रह रहे हैं। लोकतंत्रा के माध्यम से गरीबों, असहाय, पिछड़े और वंचित लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। गरीब, वंचित, पिछड़े लोग इस अवसर का लाभ उठाने लगे और मुख्यधारा में आने लगे। दिन-ब-दिन और साल-दर-साल कई बदलाव हुए, सरकारें बदलीं, मुखौटे बदल गए, हम लोगों के लिए यह करेंगे, हम वो करेंगे, सिर्फ काम करने का तरीका बदला है, लेकिन सोचने का तरीका नहीं बदला है। क्योंकि प्रवृत्ति वैसी ही प्रतीत होती है। जैसे ही 100 गरीब अमीर बन गए, गरीबी खत्म नहीं हुई। जिन्हें 70-72 साल पहले आरक्षण मिला था, वे आज भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और जिन्हें आरक्षण नहीं मिला वे अभी भी 70-72 साल से वंचित हैं। यह स्थिति बिल्कुल भी बदलती नहीं दिख रही है। क्योंकि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वास्तव में बहुत अधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन सत्ता के लिए वोटों का राजनीतिकरण करने की प्रवृत्ति ही एकमात्रा बाधा है...

ओबीसी समुदाय के राजनीतिक आरक्षण को लेकर गरमागरम चर्चा चल रही है। हर तरफ कहा जा रहा है कि मौजूदा राज्य सरकार इस मामले में विफल रही है। तथ्य यह है कि पिछली देवेंद्र फडणवीस गठबंधन सरकार उच्च न्यायालय में 32 प्रतिशत मराठा समुदाय के लिए 12-13 प्रतिशत आरक्षण बनाए रखने में कामयाब रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज ओबीसी समुदाय के साथ भी यही हो रहा है।

भले ही आरक्षण स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन जिन गणमान्य व्यक्तियों ने 27 प्रतिशत ओबीसी समुदाय के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, उनसे अनुरोध है कि वे बिना किसी आरक्षण के मराठा समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मराठा समुदाय को भी न्याय दें।

ला.प्रतिक कदम मल्टीपल लायन्स इंटरनेशनल महाराष्ट्र के बेस्ट चेयरपर्सन ट्राफी से सन्मानीत

केन्द्रीय राज्य अर्थ मंत्री लॉयन भागवत कराड ने किया सत्कार

बुलंद गोंदिया - लायंस क्लब मल्टीपल 3234 का क्षेत्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित किया गया था। जिसमें एमजेएफ प्रतिक कदम को बेस्ट चेयर पर्सन ऑफ मल्टीपल महाराष्ट्र के उत्कृष्ट प्रांतीय सदस्य के लिए गोल्ड ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मल्टीपल में उत्कृष्ट कार्य व पोर्टफोलियो के साथ डिस्ट्रिक गवर्नर राजेंद्र बग्गा को भी सक्रिय सहयोग देने पर सम्मानित किया गया। उपरोक्त सम्मान केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड द्वारा देकर सत्कार किया गया। उल्लेखनीय है कि मुंबई को छोड़कर शेष महाराष्ट्र जिसे 4 विभागों में बांटा गया जिसमें डी1, डी2, एच1, एच2 के नाम से जाना जाता है। इन संपूर्ण मल्टीपल का क्षेत्रीय सम्मेलन औरंगाबाद में आयोजित किया गया था। जिसमें नेपाल के इंटरनेशनल डायरेक्टर संजय खेतान, भारत के इंटरनेशनल डायरेक्टर नरेंद्र भंडारी पुणे, इंटरनेशनल डायरेक्टर नवल मालू औरंगाबाद, पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर प्रेमचंद बाफना पद्मश्री पदक, जयेश ठक्कर नांदेड़, काउंसिल चेयर पर्सन विवेक अभ्यंकर, नासिक से गिरीश मालपानी, जालना से दिलीप मोदी व नवनिर्वाचित मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन उपस्थित थे।

इस उपलब्धि पर प्रतीक कदम ने पूर्व पीएमसीसी राजे मूधोजी भोसले नागपुर, पीएमसीसी डॉ. लक्ष्मीकांत राठी अमरावती, पीएमसीटी डॉ. विनोद आदलखिया वर्धा, पीएमसीटी एड. संदीप खंडेलवाल नागपुर, रिपल राणे आर्वी, श्रवकुमार डीजी इलेक्ट नागपुर, कालूराम अग्रवाल का मार्गदर्शन मिलने पर आभार माना। बेस्ट केबिनेट ऑफिसर ऑफ मल्टीपल के विजेता होने पर लायन कालूराम अग्रवाल, विनोद जैसवाल, प्रशांत पांडे, संतोष

कायते, स्नेहित रोकडे, मनोज दुर्गानी, प्रदीप जायसवाल, मनोज डोहरे, दीपक कदम, दिलीप चौरागड़े, सुनीता अग्रवाल, प्रल्हद सारवे, पुष्पक जसानी आदि सदस्यों ने गोंदिया जो की महाराष्ट्र के बॉर्डर पर होकर भी अपनी कार्य शैली से लायंस गतिविधि के कार्य से सम्पूर्ण महराष्ट्र मे नाम आलौकिक करने पर शुभकामनायें देकर हर्ष व्यक्त किया।

सामाजिक व बहुउद्देशीय कार्यों के लिए जननी सहयोग संगठन की स्थापना

बुलंद गोंदिया - विश्व मातृत्व दिवस के अवसर पर सामाजिक व बहुउद्देशीय कार्य तथा महिलाओं की समस्याओं संबंधित जन जागृति व समस्याओं के निवारण के लिए जननी सहयोग संघटना की स्थापना रीता सुधीर बागड़े के संयोजन ने किया गया। संगठन के प्रमुख उद्देश्यो की जानकारी देते हुए संयोजिका रीता सुधीर बागड़े ने बताया कि संगठन के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को स्कूली कॉपी किताबें उपलब्ध कराना, कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार, मतिमंद व मंदबुद्धि मूक-बधीर बच्चों की उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा विशेषकर महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण व जनजागृति के साथ सेनेटरी पैड के प्रति जागरुक करना व गरीब वर्ग के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा के क्षेत्रा में सहायता करना जननी सहयोग संघटना का मुख्य उद्देश्य होंगा।

संघटना के स्थापना व विश्व मातृत्व दिवस के अवसर पर संगठन द्वारा गोंदिया के शासकीय महिला चिकित्सालय बाई गंगाबाई में प्रसूता महिलाओं को सेनेटरी पैड देकर मातृत्व दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संघटना की संयोजिका रीता सुधीर बागडे, अर्चना ठाकरे, भावना कदम, उमा महाजन, मंदा गायधने, पूनम पांडे, पूजा चंद्रवंशी, श्रद्धा मिश्रा, आशा मिश्रा, मोनिका ब्राम्हणकर, शुभांगी कोरे आदि महिलाएं प्रमुख रुप से उपस्थित थी।

चिचगढ़ पुलिस के आशीर्वाद से मवेशियों का अवैध परिवहन जोरों पर

नियमों का खुलेआम उल्लंघन

बुलंद संवाददाता देवरी - चिचगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत छत्तीसगढ़ से ककोड़ी चिचगढ़ मार्ग से मवेशियों का अवैध परिवहन जोरो से शुरु है। उपरोक्त परिवहन को चिचगढ़ पुलिस का आशीर्वाद प्राप्त होने का आरोप चिचगढ़ पुलिस स्टेशन सीमा अंतर्गत के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। मध्य रात्रि में 2 से 5 के दौरान मवेशियों का अवैध परिवहन शुरु है। जबकि कानून के अनुसार मवेशियों का अवैध परिवहन पर प्रतिबंध है। उसके बावजूद ककोड़ी चिचगढ़ मार्ग से बड़े पैमाने पर मवेशियों का अवैध रुप से परिवहन शुरु है। इसमें शासन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर वाहनों में मवेशियों को अवैध रुप से बेदर्दी से भरकर ले जाया जा रहा है। इस प्रकार की चर्चा चिचगढ़ ककोड़ी ग्रामों में जोरों से चल रही है। उल्लेखनीय है कि इस पर प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी चिचगढ़ पुलिस थाने के अधिकारियों व कर्मचारियों की है। किंतु मवेशियों के अवैध परिवहन से मिलनेवाली मलाई के चलते शासन के नियमों की अनदेखी कर अवैध रुप से मवेशियों की तस्करी करनेवाले वाहन चालकों को आशीर्वाद दिया गया है। यह गंभीर प्रकरण चिचगढ़ के पुलिस निरीक्षक के आंखों के सामने चल रहा है, किंतु पुलिस निरीक्षक द्वारा इस पर कार्यवाही न कर, इस गंभीर मामले को अपना समर्थन दे रहे हैं। वे कुछ महीने पूर्व ही

नियुक्त हुए हैं। इस मामले में क्षेत्र के उप विभागीय पुलिस अधिकारी संकेत देवलेकर इस ओर ध्यान देंगे तथा भविष्य के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने की मांग ककोडी चिचगढ़ के नागरिकों द्वारा की गई है।

बजरंग दल द्वारा पकड़े मवेशियों के वाहन

ककोड़ी से चिचगढ़ मार्ग पर चिखाढ टी-प्वाईंट के समीप अवैध मवेशियों का परिवहन करने वाले वाहन जिसमें मवेशियों को भर कर ले जाया जा रहा था। ऐसे 26 मवेशियों सहित वाहन को बजरंग दल द्वारा पकड़ा गया था। जिस पर चिचगढ़ पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर वाहन को कब्जे में लिया था। किंतु इसके बावजूद भी रात के दौरान मवेशियों की अवैध तस्करी जोरों से शुरु है तथा इसमें कौन-कौन शामिल है, इस पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो रहा है।

रात्रि गश्त पर प्रतिबंध

चिचगढ़ पुलिस स्टेशन यह नक्षलग्रस्त क्षेत्र में आने के चलते रात में पुलिस गश्त के लिए पुलिस कर्मचारियों पर प्रतिबंध है। पुलिस थाने में शिकायत प्राप्त होने पर उपरोक्त शिकायत पर तत्काल कार्रवाई चिचगढ़ पुलिस विभाग द्वारा की जाती है।

- अजय भुसारी, पुलिस निरीक्षक चिचगढ़

उषाकिरण आत्राम का अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन शिमला के लिए चयन

बुलंद संवाददाता दरेकसा - साहित्य अकादमी दिल्ली के माध्यम से अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर 16 जून से 18 जून 2022 तक तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित किया गया है। उपरोक्त सम्मेलन में देश भर के साहित्यकार सहभागी होंगे, जिसमें विभिन्न राज्यों के आदिवासी साहित्यकार अपने साहित्य के साथ उपस्थित रहेंगे तथा कविता कथा चर्चा सत्र विषयों पर चर्चा होंगी। उपरोक्त सम्मेलन में गोंदिया जिले की आदिवासी साहित्यकार उषाकिरण आत्राम का चयन हुआ है। उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रण प्राप्त हुआ। वे इस सम्मेलन में गोंडी भाषा की अपनी कविता प्रस्तुत करेंगी। उनके इस चयन पर जिले के विभिन्न साहित्यकारों ने उनका अभिनंदन किया है। जिसमें प्राध्यापक माणिक गेडाम, नवल किशोर, राजेश मडावी चंद्रपुर, गोंडवाना दर्शन के बीजू बूढ़े, नंदकिशोर नेताम, अमित वैद्य, पवन पाथोडे किरण मोरे ने शुभेच्छा दी है।

जिला परिषद गोंदिया के सार्वजनिक बांधकाम विभाग में नियमबाह्य पदोन्नति

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिला परिषद प्रशासन हमेशा ही अपने विवादास्पद कार्यप्रणाली के चलते चर्चा में बना रहता है। इसी प्रकार का एक मामला जिला परिषद के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंतर्गत आने वाली जिले की आठ पंचायत समिति के कार्यालयों में स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्ग में 24 पद मंजूर है। जिसमें से 10 सहायक अभियांत्रिकी को नियम और शर्तो के अंतर्गत रहकर पदोन्नति देने की कार्रवाई जिला परिषद स्तर पर शुरु है।

उपरोक्त पदोन्नति प्रक्रिया नियम और शर्तो के अधीन रहकर पदोन्नति देने के लिए आयुक्त की मान्यता की मंजूरी आवश्यक होती है, जिसमें जो कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र है तथा जिन्होंने अप्रैल 2022 में विभाग द्वारा लिया गया है तथा उन्हें विभागीय परीक्षा दी है। किन्तु ऐसे कर्मचारियों को न लेते हुए तथा आयुक्त की लिखित परवानगी मंजूरी न लेते हुए नियमबाह्य पद्धति से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल पाटिल द्वारा नियम के खिलाफ पदोन्नति दी जा रही है ऐसी जानकारी सामने आई है। जिसके चलते पात्र कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है कि इस प्रकार की नियमबाह्य पदोन्नति न दी जाए, जिससे भविष्य में पात्र कर्मचारियों के लिए रिक्त स्थान शेष न रहे व अन्य कर्मचारियों पर अन्याय न हो।

५ पंचायत समितियों के सभापति निर्वाचित

भाजपा ५, जनता की पार्टी चाबी संघटना १, कांग्रेस १ व भाजपा समर्थित १

बुलंद गोंदिया टीम - गोंदिया जिले की 8 पंचायत समितियों के सभापति और उपसभापति का चुनाव 6 मई को संपन्न हुए। जिसमें गोरेगांव तिरोड़ा देवरी आमगांव व सड़क अर्जुनी इन पांच पंचायत समितियों पर भाजपा के सभापति व उपसभापति, चाबी संघटना जनता की पार्टी के गोंदिया पंचायत समिति में सभापति व राष्ट्रवादी कांग्रेस का उपसभापति तथा सालेकसा पंचायत समिति में कांग्रेस के सभापति व उपसभापति तथा अर्जुनी मोरगांव पंचायत समिति में भाजपा समर्थित वंचित बहुजन आघाडी के सभापति व भाजपा समर्थित निर्दलीय उपसभापति निर्वाचित हुआ है। जिसके चलते हैं जिले की 8 में से 6 पंचायत समितियों पर भाजपा का कब्जा हुआ है। गोंदिया पंचायत समिति गोंदिया पंचायत समिति में गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल व प्रफुल पटेल के निर्देशानुसार पूर्व विधायक राजेंद्र जैन द्वारा पंचायत समिति चुनाव की कमान संभाली गई। जिसमें जनता की पार्टी चाबी संघटना के मुनेश रंहागडाले सभापति व राष्ट्रवादी कांग्रेस के नीरज उपवंशी विजयी हुए, जिन्हें चाबी संघटना राष्ट्रवादी कांग्रेस बसपा व निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ तथा दोनों विजयी उम्मीदवारों ने 18-18 मत प्राप्त किया। दोनों विजयी उम्मीदवारों को विधायक विनोद अग्रवाल व पूर्व विधायक राजेंद्र जैन द्वारा शुभकामनाएं दी गई।

तिरोडा व गोरेगांव पंचायत समिति तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तिरोड़ा व गोरेगांव पंचायत समिति में भाजपा की ओर से चुनाव की कमान क्षेत्र के विधायक विजय राहंगडाले द्वारा संभाली गई थी। जिनके मार्गदर्शन में दोनों पंचायत समितियों में भाजपा के सभापति व उपसभापति निर्वाचित हुए, जिसमें तिरोड़ा पंचायत समिति में कुंताबाई रामप्रकाश पटले सभापति व हूपराज रामजी जमाईवार उपसभापति तथा गोरेगांव पंचायत समिति में मनोज श्यामलाल बोपचे सभापति व राजकुमार रामविलास यादव उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोनों पंचायत समिति में निर्वाचित पदाधिकारियों को विधायक विजय राहंगडाले द्वारा शुभकामनाएं दी गई।

सड़क अर्जुनी व अर्जुनी मोरगांव पंचायत समिति अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो पंचायत समितियों का समावेश है, जिसमें दोनों पंचायत समितियों के चुनाव में भाजपा की ओर से पूर्व विधायक राजकुमार बडोले के मार्गदर्शन में सड़क अर्जुनी में संगीता खोब्रागड़े सभापति व सलिन्दर कापगते उपसभापति निर्वाचित हुए। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान भाजपा तहसील अध्यक्ष अशोक लंजे, जीवन लंजे, लक्ष्मीकांत हर्ष मोदी, मिलन, राहुल, विलास, सुनील भिवगड़े भाजपा के कार्यकर्ता प्रमुख रुप से उपस्थित थे। अर्जुनी मोरगांव पंचायत समिति का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होने के चलते भाजपा द्वारा वंचित बहुजन आघाडी से निर्वाचित सविता कोडापे को सभापति पद के उम्मीदवार के रुप में समर्थन दिया तथा वहीं भाजपा के बागी उम्मीदवार के रुप में निर्दलीय विजयी हुए। होमराज पुस्तोडे को उपसभापति पद के लिए समर्थन दिया, जिससे भाजपा समर्थन से दोनों उम्मीदवार विजयी हुए।

आमगांव, देवरी व सालेकसा पंचायत समिति आमगांव-देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 पंचायत समितियों का समावेश है। जिसमें में भाजपा की ओर से चुनाव की बागडोर पूर्व विधायक संजय पुराम द्वारा संभाली गई। जिसमें आमगांव देवरी में भाजपा के सभापति व उपसभापति निर्वाचित हुए। जिसमें देवरी में अंबिका बंजार सभापति व अनिल बिसेन उपसभापति, आमगांव में राजेंद्र गौतम, सभापति नोहरलाल गौतम उपसभापति निर्वाचित हुए। सालेकसा पंचायत समिति में कांग्रेस की प्रमिला गणवीर सभापति व संतोष बोहरे उपसभापति निर्वाचित हुए।

डेढ़ वर्षीय नाबालिका को शराबी रोड रोलर चालक ने कुचला

सालेकसा तहसील के दलदलकुही ग्राम में घटित हुआ हादसा

बुलंद संवाददाता दरेकसा - सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले दरेकसा के समीप ग्राम दलदलकुही में 6 मई की दोपहर 12 बजे के दौरान शराबी रोड रोलर चालक द्वारा डेढ़ वर्षीय नाबालिगा को कुचल दिया जिससे उससे उसकी मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम में डामर रोड के किनारे मुरुम डालकर उसे सपाट करने का कार्य रोड रोलर द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान 12 के दौरान ग्राम की डेढ़ वर्षीय नाबालिगा जिया इंद्रपाल ऊईके रोलर के नीचे आकर दब गई। उपरोक्त रोड रोलर दहेगांव निवासी ड्राइवर युवराज कांबले (30) चला रहा था जो शराब के नशे में था। उपरोक्त कार्य गोंदिया की आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा था। उपरोक्त घटना के घटित होते ही ग्राम के नागरिक उग्र होकर आक्रोशित हो गए थे तथा ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया जिसमें बताया गया कि रोलर के पीछे एक कामगार चलता है, लेकिन उपरोक्त कार्य के दौरान रोलर के पीछे कोई नहीं था। यदि पीछे कोई कामगार होता तो उपरोक्त घटना घटित नहीं होती। घटना की जानकारी सालेकसा पुलिस थाने को मिलते ही मृतक नाबालिगा का शव सालेकसा वेः ग्रामीण चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 3 बजे के दौरान आमगांव के उपविभागीय अधिकारी, सालेकासा के पुलिस निरीक्षक व दरेकसा पुलिस वैंप वेः अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की संपूर्ण जानकारी लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा उपरोक्त प्रकरण में भादवि की धारा 279 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच सालेकसा पुलिस द्वारा शुरु की गई है।

बोगस डॉक्टर व दुष्कर्मी तांत्रिक को २९ वर्ष का सश्रम कारावास व १.१४ लाख का जुर्माना

बुलंद गोंदिया - गोंदिया तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम फूलचुर निवासी आरोपी बोगस चिकित्सक व तांत्रिक मुकेश उर्फ लंकेश मेश्राम (35) को 17 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 मई को सुनाया। अपने फैसले में प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश एसएएआरओटी द्वारा दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 29 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख 14 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी की पीड़िता नाबालिका 17 वर्षीय की छाती के समीप गांठ होने से उसका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ते रहता था। उसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर चिकित्सकों के पास जाकर उपचार करवाया, किंतु किसी भी प्रकार का फायदा न होने पर पीड़िता की दादी जहां काम पर जाती थी, उस व्यक्ति की सलाह पर उपरोक्त आरोपी से दवाई लेने पर बीमारी में आराम होता है, ऐसा बताए जाने पर पीड़िता की माता व दादी द्वारा उपरोक्त बोगस डॉक्टर आरोपी पर विश्वास रखते हुए 27 मार्च 2019 को लंकेश मेश्राम को अपने घर पर बुलवाया।

पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक न होने से वह पलंग पर ही आराम करती थी। जिसका आरोपी द्वारा फायदा लेकर अश्लील हरकत कर दुष्कर्म किया। उपरोक्त चिकित्सा के दौरान आरोपी द्वारा घर के अन्य लोगों को उपरोक्त कक्ष के बाहर ही रखने व अकेला कक्ष में प्रवेश करता था तथा हिदायत देता था कि इस दौरान वे अंदर न आए तथा आरोपी द्वारा घर के अन्य लोगों व पीड़िता को काले रंग की एक बेहोशी की दवा देकर घर के सामने का दरवाजा बंद कर किसी को अंदर आने नहीं देता था। इस प्रकार आरोपी द्वारा 27 मार्च 2019 से 5 अप्रैल 2019 तक पीड़िता व उसके घर के सभी लोगों को बेहोशी की काली गोली देकर पीड़िता पर बार-बार दुष्कर्म किया। पीड़िता व घर के लोगों को बेहोशी की गोली दिए जाने के चलते अन्य लोगों को इस बात की जानकारी दे नहीं सकती थी। किंतु 5 अप्रैल 2019 को पीड़िता के रिश्तेदार चाचा बाहर गांव से दोपहर के समय पीड़िता के घर पर आए तथा उन्हें घर के सामने के दरवाजे पर ताला लगा दिखाई दिया। जिससे आसपास के लोगों को लोगों से पूछताछ किए जाने पर 8 दिनों से दरवाजा बंद होने की जानकारी सामने आई। जिस पर पीड़िता के रिश्तेदारों द्वारा दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। जहां आरोपी सामने आया तथा यह बात सामने आई कि आरोपी द्वारा परिवार और पीड़िता को बेहोशी की दवाई देकर बार-बार दुष्कर्म कर रहा है। यह बात सामने आते ही इस घटना की जानकारी गोंदिया शहर पुलिस थाने को फोन पर दी तथा पुलिस को बुलाकर पीड़िता का उपचार किया तथा आरोपी बोगस चिकित्सक व तांत्रिक की बात सामने आने पर तथा उनके परिवार की अज्ञानता का लाभ लेकर बेहोशी की दवाई देकर दुष्कर्म अत्याचार करने की बात सामने आई। जिसके पश्चात पीड़िता द्वारा 5 अप्रैल 2019 को गोंदिया शहर पुलिस थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई उपरोक्त शिकायत के आधार पर तत्कालीन महिला पुलिस उपनिरीक्षक सांदिया सोमनकर द्वारा आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376, (2), (एन), 342, 343, 328, 506 व बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 व 6 के तहत संपूर्ण जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

उपरोक्त प्रकरण में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने व पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील सतीश यू. घोड़े व विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी द्वारा 8 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। चिकित्सा अहवाल व पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए प्रमुख जिला वह विशेष सत्र न्यायधीश एसएएआरओटी द्वारा 29 वर्षो का सश्रम कारावास व 1 लाख 14 हजार दंड की सजा सुनाई। जिसमें बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना दंड की राशि न भरने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भादवि की धारा 328 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भादवि की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कारावास व 2000 जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास, भादवि की धारा 343 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 जुर्माना न भरने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि प्राप्त होने पर उपरोक्त राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। साथ ही मनोधैर्य योजना के अंतर्गत पीड़िता की चिकित्सा उपचार को पुनर्वासन के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण को उचित सहायता करने का आदेश दिया। उपरोक्त मामले में पैरवी कर्मचारी मपोहवा श्रीमती पटले, पोसि रामलाल किरसान पुलिस स्टेशन गोंदिया शहर द्वारा विशेष सहयोग दिया गया।

प्रफुल पटेल के प्रयासों से २.३५ करोड़ के निधि मंजुर

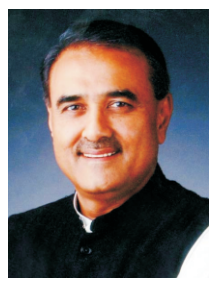

बुलंद गोंदिया - गोंदिया व भंडारा दोनों जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबंध सांसद प्रफुल पटेल द्वारा श्रृंखलाबद्ध निरंतर विकास कार्यो को गति देने का कार्य शुरु है। जिसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गोंदिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यो को मंजूरी देने के लिए पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा सांसद प्रफुल पटेल के समक्ष निवेदन किया था। जिस पर सांसद पटेल के प्रयासों से राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6 मई को जारी किए गए शासन निर्णय के अनुसार गोंदिया जिले के कुल 47 विकासात्मक कार्यो के लिए 2 करोड़ 35 लाख की निधि को प्रशासकीय मान्यता दी है।

जिसमें गोंदिया ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग व अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्य जल्द ही शुरु होंगे। सांसद पटेल के प्रयासों से निधि प्राप्त होने पर जिलेवासियों द्वारा उनका आभार व्यक्त किया है। गोंदिया-भंडारा दोनों जिलों में सांसद पटेल सर्व सामान्य नागरिकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं तथा कोरोना काल में भी दोनों जिलों को अनाथ न छोड़कर निरंतर मदद के लिए अग्रसर रहें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर नागरिकों से संवाद निरंतर रखा है। उसी के अनुसार पूर्व विधायक राजेंद्र जैन द्वारा भी जिले की समस्या सांसद पटेल के सामने रखी जाती है। जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सांसद पटेल द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से मांग की थी। जिसके तहत गोंदिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मार्गो व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए किए गए प्रयासों से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6 मई को शासन निर्णय जारी कर जिले के लिए कुल 47 कामों को प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कर उसके लिए 2 करोड़ 35 लाख की निधि मंजूर की है, तथा सार्वजनिक बांधकाम विभाग के माध्यम से उपरोक्त कार्य पूर्ण किए जाने का निर्देश भी दिया गया है।

47 विकास कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए लेखा सिर्फ 2515 वह 1238 योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है। जिसमें दो सभागृह, एक मार्ग पुल, दो सुरक्षा दीवार, एक श्मशान भूमि सौंदर्यकरण, नाली बांधकाम, बुद्धविहार सौंदर्यीकरण व 38 मार्ग सीमेंटीकरण का समावेश है। मंजूरी प्रदान किए गए कार्यो में गोंदिया तहसील 17, तिरोड़ा तहसील 7, सड़क अर्जुनी तहसील 4, अर्जुनी मोरगांव 3, आमगांव 9, गोरेगांव 6, सालेकसा तहसील में 1 कार्यो का समावेश है।

गुदमा के सरकारी तालाब से बगैर रायल्टी मुरुम का उत्खनन

बुलंद गोंदिया - जिले में अवैध उत्खनन की चर्चा आम हो चुकी है। बगैर रॉयल्टी अवैध उत्खनन से करोडों का राजस्व डुबाए जाने को लेकर हमेशा से राजस्व विभाग संदेह में घिरा रहा है। इन दिनों तहसील के गुदमा में स्थित सरकारी सावरी तालाब का मामला गरमाया हुआ है। बताया जाता है कि बगैर रायल्टी रेलवे के ठेकेदारो द्वारा यहां से सैकडों ब्रास मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है। तालाब से 24 घंटे पोकलैंड मशीन से खुदाई किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश पनपता नजर आ रहा है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा लोहमार्ग के किनारे रेल लाईन के लिए गुदमा के सरकारी सावरी तालाब से ठेकेदारों द्वारा मुरुम का उत्खनन किया जा रहा है। लेकिन रायल्टी के संबंध में पूछताछ करने के दौरान ठेकेदार और संबंधित विभाग के अधिकारी दोनों ही स्पष्ट उत्तर देने से बचते नजर आए।

गौरतलब है कि मुंबई-हावडा लोहमार्ग पर स्थित गोंदिया रेलवे स्टेशन से आमगांव रेलवे स्टेशन तक विगत अनेक दिनों से तीसरी रेलवे लाईन बिछाने के लिए पुल और चौडीकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त काम ठेकेदारों के माध्यम से हो रहा है। लोहमार्ग के किनारे की जगह को चौडी करने के लिए मिट्टी और मुरुम का बडे पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। गोंदिया तहसील के ग्राम गुदमा में सरकारी सावरी तालाब गट क्र 891, 892, 893 हे. आर.चौ.मी 620 सरकारी जमीन पर स्थित है। अधिकार अभिलेख पत्रक में दर्शायी गयी खेत जमीन सिर्लींग भूधारक (161) उल्लेखित होने का बताया जा रहा है। सरकारी रिकार्ड में दर्ज जमीन पर पिछले एक माह से अधिक समय से रेलवे के ठेकेदारों व्दारा पोकलैंड से 24 घंटे मुरुम खुदाई का कार्य किया जा रहा है।

मुरुम खुदाई के लिए किसानों के खेतों की मेढो को तोडा गया है। पोकलैंड से खोदे गए मुरुम का टिप्परों से उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन और मशिनों की आवाज की वजह से ग्रामीणों की नींद उड़ चुकी है। तालाब से धडल्ले से हो रहे अवैध उत्खनल पर संदेह जताते हुए ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित ठेकेदार व्दारा अब तक कितने ब्रास मुरुम खोदा गया या खोदा जाना है, स्पष्ट नहीं किया गया है। चर्चाओं में राजस्व विभाग एवं ठेकेदार की मिलीभगत होने की बात सुनाई पड़ रही है। शासन और प्रशासन के आंखो में धूल झोंक सैकडों ब्रास मुरुम खुदाई से शासन का करोडों का राजस्व डुबाए जाने का अंदेशा भी ग्रामीणों द्वारा जताया गया है। विगत अनेक दिनों से हो रहे अवैध मुरुम उत्खनन से राजस्व विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में नजर आ रही है।

मुरुम खुदाई की ली अनुमति

तालाब से मुरुम खुदाई की ग्राम पंचायत से अनुमति ली गयी है। पोकलैंड से मुरुम खुदाई का कार्य किया जा रहा है। टिप्परों से मुरुम का परिवहन किया जा रहा है। तालाब से मुरुम खुदाई से पूर्व अपर जिलाधिकारी राजेश खवले को भी जानकारी दी गई है।

- रविंद्र अन्ना, ठेकेदार रेलवे विभाग

आरटीई के तहत मांगे जानकारी

ग्राम गुदमा के सावरी तालाब से रेलवे ठेकेदार द्वारा मुरुम उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। रायल्टी से संबधित जानकारी आरटीई के तहत तहसीलदार, खनिकर्म विभाग और एसडीएम से लेनी चाहिए। ठेकेदार ने रायल्टी से अधिक खोदकाम किया है, तो खोदकाम के हिसाब से राजस्व वसूला जाएगा।

- राजेश खवले, अपर जिलाधिकारी, गोंदिया

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।